II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways (Railway Board) Notification G.S.R. No. 200, dated the 21st January, 1978. [*Placed in Library. See* No. LT-1519/78.]

Prevention of Food Adulteration (Third Amendment) Rules, 1977

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : श्रीमन्, मै आपकी अनुमति से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण (तृतीय संशोधन) नियम, 1977 को प्रकाशित करने वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 775 (ई), दिनांक 27 दिसम्बर, 1977 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं। [*Placed in Library. See* No. LT-1555/78.]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported fast deteriorating economic conditions of Cane Growers as a result of sharp fall in prices of Gur and Khandsari

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : सभापति महोदय, मैं दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में गुड़ और खंडसारी के भाव एकदम गिर जाने के फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों की तेजी से बिगड़ती हुई आर्थिक दशा तथा उनके हितों की रक्षा के लिये किये गये उपायों की ओर कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): Sir, the Government are fully conscious of the important role played by Sugarcane crop in the agricultural economy of India. On this crop depends the welfare of about 25—30 million farmers. In many parts of our country, this is perhaps the most important, if not the only, cash crop. In recent years, the area under sugarcane yield per acre and the total output have been going up steadily. These have been possible due to a number of factors including the growth of the sugar industry, the remunerative prices paid to sugarcane growers, particularly by the organised sector of the industry etc. Unfortunately, however, recent developments throw doubts on whether such a growth in cane area would be economically justifiable. During the current 1977-78 sugar year, from the information so far, available, it appears that the area under sugarcane which was about 29 lakh hectares in 1976-77 would have gone up to 31-32 lakh hectares. The production of sugarcane is also expected to be higher by about 10-11 million tonnes, at 165 million tonnes. The spurt in production by 10 million tonnes, has, it is to be conceded, led to an anxious situation, through the absorption difficulty of this by all the sweetening agencies in a coordinated manner. The expectation is that the sugar industry would find an extra outlet for about half the additional quantity of sugarcane. For various reasons including the present Government's policy to make essential commodities available to a wide spectrum of community at reasonable prices, enlargement of the coverage of the public distribution system, liberal release of sugar for domestic consumption etc., prices of sweetening agents have shown a downward trend. While to a certain extent, the fall in the consumer price is welcome, it is the endeavour of this Government to ensure that they do not fall to such levels as to affect adversely the price for cane. The prices of khandsari and gur have fallen in the last two months by Rs. 40 to 60 per quintal in the case of sulphur khandsari and of gur by about Rs. 25—40 per quintal. With a view to correct the imbalances, the Government have taken a series of measures, the more important of which are the following:

(i) allowing the export of gur outside the country;

[Shri Bhanu Pratap Singh]

(ii) to make market purchase of gur by public sector agencies with a view to stablise its prices; and

(iii) reduction in excise duty on both types of khandsari.

As early as July 1977, when a accumulation of stocks of gur was noticed in some of the principal gur producing States, a small quantity of gur was allowed to be exported on experimental basis to assess its effect on markets. Subsequently, early in December 77, export of 5,000 tonnes of gur was permitted canalising it through the State Trading Corporation. Recently, gur export has been allowed through private trade channels also. Quota limits and price restrictions have been withdrawn fully on exports.

The National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd. (NAFED) has also been instructed to purchase gur in adequate quantities. However, the scale of operations so far has not produced the desired results.

The Government have also reduced excise duty on sulphur and desi khandsari substantially. The effect of these reductions would make the average incidence of excise duty at Rs. 10/-and Rs. 5/- respectively per quintal for sulphur and desi khandsari. However, there is very limited scope left for further relief in this direction, considering the repercussions by way of possibility of imposition of sales tax by the State Governments.

It is hoped that the State Governments would also waive the sales tax on gur wherever it is levied. The Government of India are in close touch with the State Governments and are reviewing the developments continuously.

श्री सुलतान सिंह : सभापति महोदय, इस साल जबसे यह जनता सरकार आई है किसानों को करोड़ों रुपये का केवल खंडसारी और गुड़ में नुक्सान हुआ है । इसके साथ-साथ इस सरकार ने बार-बार ग्रामोद्योग का प्रचार किया । गांवों का सबसे बड़ा उद्योग क्रैशर है । एक-एक गांव में 10-10, 15-15 क्रैशर चलते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में खासकर । आज जितने क्रैशर हैं वे फेल होने जा रहे हैं उनके पास कोई आमदनी नही है । किसान करोड़ों रुपये के नीचे आ गया है । अपने जिस खेत में वह कनक बोता था, अब की बार वह फसल निकाल कर कनक नहीं बोएगा क्योंकि इस बार वह बुरी तरह से बरबाद हो रहा है । यह जनता सरकार बार-बार कहती है कि पहली बार किसानों के हित की सरकार आई है । मैं समझता हूं पहली बार ऐसी सरकार आई जिसके आने के बाद किसान इतनी बुरी तरह से बरबाद हुआ है जितना आज तक नहीं हुआ । पिछली बार गेहूं का भाव 107-108 रु० रहा जो किसानों से खरीदा गया और बाजार में 150 रुपये क्विंटल बेचा गया । एक महीने के अन्दर आप देखेंगे कि अब जो फसल आ रही है इसके भाव और नीचे आ जायेंगे । इसी प्रकार किसानों की जो सरसों है उसके भाव भी नीचे आ गये हैं । इसी तरह से कोट्न के भाव भी 650 रुपये क्विंटल हो गये हैं । जहां सबसे ज्यादा कोट्न पैदा होता है वहां एक दम 100 परसेंट दाम नीच आ गये हैं । जब तक कोट्न ग्रोअर को पैसा नहीं मिलेगा तो वह कोट्न क्यों पैदा करेगा । जो कोट्न खरीदते हैं वह कोट्न ग्रोअर को पैसा नही देते । इसी तरह से जो क्रैशर वाले हैं वह गन्ना उत्पादकों को पैसा नहीं देते । पिछले साल क्रैशर वालों ने 14-15 रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदा था और अब 6 से 7 रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीद रहे है । यह सब सरकार की आंखों के नीचे हो रहा है । चारों तरफ तूफान उठा हुआ है । अपने मुजफ्फरनगर में, बुलन्दशहर में, मेरठ में, बिजनौर में, ईस्टर्न यू० पी० और हरियाणा में चारों तरफ किसान चिल्ला रहे है । इस बारे में सरकार शर्म महसूस नहीं करती । सरकार कहती है कि पहली बार किसानों को प्राथमिकता मिली है । मुझे बताया जाए कि किस चीज में

प्राथमिकता मिली है । क्या ट्रैक्टर के रेट्स कम हुए है, क्या इन्सेक्टीसाइड्स की कीमत कम हुई है, क्या खाद की कीमत कम हुई है, क्या वाटर रेट्स कम हुए हैं, क्या लैंड रेवन्यू कम हुआ है ? एक बात यह बता दीजिए कि किसान को किस चीज में प्राथमिकता मिली है । आज किसान चिल्ला रहा है । यह जनता सरकार की साजिश है क्योंकि व्यापारी वर्ग के कंट्रोल मे यह सरकार है । मैं रिकार्ड के लिये बताता हूं कि दो महीने के बाद गुड का भाव फिर तेज होगा क्योंकि दो महीने के बाद यह एक्सपोर्ट होगा । इस देश से गुड़ बाहर जाएगा । इसलिये सरकार अपनी स्पष्ट नीति बताए यह मेरी आपसे प्रार्थना है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, जहां तक तिलहन, कपास इत्यादि चीजों का सम्बंध है, इनकी चर्चा मैं इस समय नही कर रहा हूं क्योंकि यह उपयुक्त अवसर नही है । अवसर आने पर उनके संबंध में भी उत्तर दे दूंगा । इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गुड की है । इसमे कोई संदेह नही कि इस बारे मे किसान काफी कष्ट मे है और उस कष्ट के लिए उस तरफ के माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि इस समस्या के लिए जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है । मै उनकी इस बात को पूर्णतया स्वीकार नही करता हूं । वास्तव में यह समस्या पैदा इसलिए हुई है कि . . . (*Interruptions*) । आप मेरी बात को पूरी तरह से सुन तो लीजिये । मै आपकी बात धैर्य से सुनता रहा हूं । गुड के संबंध में जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है, यह अनप्लान्ड प्लानिंग और ओवर-प्रोडक्शन के कारण हुई है । पहले जो सरकार थी उस सरकार ने यह नहीं देखा कि कितने गन्ने की खपत होगी, कितने गुड की खपत होगी और हमें कितनी चीनी की आवश्यकता होगी । वे अन्धाधुन्ध पैदावार बढ़ाते चले गये । अब हमने यह सोचा है कि भविष्य में कृषकों को यह मशविरा दिया जाय कि कौन-सी फसल बोने से लाभ होगा और कौन-सी फसल बोने से तकलीफ होने की संभावना है । पिछले साल ज्यादा गन्ना बो दिया गया, अब हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे है और जो भी बातें संभव हो सकती है वे सब की जा रही है । मैंने यह बताया है कि गुड़ पर से एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है और उसका निर्यात खोल दिया गया है । गुड़ को निर्यात करने पर कोई प्रतिबन्ध नही है । इसके अतिरिक्त सरकार खरीदारी भी करना चाहती है । ऐसी स्थिति मे अगर माननीय सदस्य आलोचना करने के बजाय कोई ठोस सुझाव देते तो उपयुक्त होता । जब जनता सरकार बनी थी तो उसके पहले गन्ना बोया जा चुका था और अब यह समस्या हमारे सामने आई है । आप जानते हैं कि पिछले छः सालों के अन्दर गन्ने का उत्पादन 46 फीसदी बढ गया है । मैं समझता हूं कि गन्ने का 46 प्रतिशत अधिक उत्पादन बढ़ाना गलत था । अपने देश की खपत को देखते हुए और निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए इस देश मे उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए । पिछले से पिछले साल यह स्थिति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे चीनी का मुल्य 10/- रु० किलोग्राम था अर्थात् 7 सौ पौण्ड पर टन । लेकिन यह गिरकर 110 और 120 के बीच में आ गया । दुनिया में कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जो चन्द सालों के अन्दर 1/5 से भी कम स्थिति मे आ गई हो । पिछले सालों में चीनी का विदेशों मे निर्यात होता रहा और विदेशी मुद्रा कमाई जाती रही । लेकिन पिछले कुछ वर्षों मे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे चीनी का मूल्य इतना उंचा हो गया कि उसका निर्यात करके भारत सरकार विदेशी मुद्रा कमा सकती थी । इसी वजह से सरकार भी गन्ने की पैदावार बढ़ाती चली गई, लेकिन उसकी खपत देश के अन्दर और विदेशों मे कम होती गई । ऐसी स्थिति में यह काम जनता सरकार ने किया है या कांग्रेस सरकार ने किया है, इसका प्रश्न नही है । अगर किसी माननीय सदस्य के पास कोई ठोस सुझाव हों तो उसका लाभ जनता को मिल सकता है । गुड़ एक

[श्री भानु प्रताप सिंह]

ऐसी कमोडिटी है जिसके संबंध में अभी यह पता नहीं है कि इसको कितने समय तक रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम यह खतरा मोल ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास इस संबंध में कोई ठोस सुझाव हों तो उनको देने की कृपा करें।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : सभापति जी, कृषि मंत्री जी इस बात को भूल गये कि पिछले साल जब गन्ने की बुआई हुई थी तो वह मार्च में हुई थी और उस वक्त उनकी सरकार बन चुकी थी।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

मैं उनको इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि खास तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के दिल में चौधरी चरण सिंह जी के लिए बड़ी श्रद्धा थी क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के अन्दर पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो गन्ने का भाव 18 और 25 रु० क्विंटल के बीच में चला गया था। इस बार भी उन्होंने सोचा कि इसी प्रकार की स्थिति होगी। इसमें किसानों ने कोई गलती नहीं की। चूंकि इस बार चौधरी चरण सिंह केन्द्र में गृह मंत्री बन चुके थे इसलिए किसानों को एक आशा बंध गई थी और इसी कारण से उन्होंने गन्ने की पैदावार ज्यादा करने की कोशिश की। तो मैं कृषि मंत्री जी से यह कहूंगा कि मेहरबानी करके किसानों के ऊपर नया मीसा न लाइये। हिन्दुस्तान के अन्दर यदि यह किया जाय कि जैसा उन्होंने कहा कि फसलों की बुवाई के अन्दर संतुलन हो तो यह एक गलत बात साबित होगी। हिन्दुस्तान गरीब किसानों का देश है, अनपढ़ किसानों का देश है। यह किसान जो फसल पैदा करता है, उसके मूल्य को सरकार पिछले 30 सालों से सही तौर पर कायम नहीं रख सकी है। तो आप फसलों की बुवाई के संतुलन के नाम से कोई दूसरा मीसा किसानों के लिये न लाइये, यह मेरा आपसे निवेदन है। मंत्री महोदय ने कहा कि कोई सुझाव दें, जिससे कि दरअसल में किसानों को राहत मिले। सुझाव बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कृषि मंत्री जी ने आंकड़े दिये कि 5 हजार टन गुड़ जो है, उसको बाहर भेजने की उन्होंने इजाजत दी है। कृषि मंत्रालय को उस समय क्या यह पता नहीं था कि 46 फीसदी गन्ना ज्यादा बो दिया गया है। तो 5 हजार टन का सुझाव देने वाले कृषि मंत्रालय को किसान क्या समझेगा और जिस मंत्रालय में आप और बरनाला जैसे मंत्री हों, तो क्या ऐसे मंत्रालय को किसानों से कोई हमदर्दी है? आज तक लोग आपको किसानों का नेता मानते है और विश्वास रखते हैं कि आप किसानों के हितों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपने जो यह ऐलान किया कि 5 हजार टन गुड़ ही बाहर भेजा जायेगा, यह कृषि मंत्रालय की सबसे बड़ी भूल है। इसके अलावा चीनी के बारे में आज का नहीं पहले का भी हिन्दुस्तान का इतिहास बताता है कि हमारे जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं जब इन्होंने कहा कि गन्ना ज्यादा हुआ है, उससे अगले ही साल गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत इतनी ज्यादा हुई कि बाहर से हमें चीनी मंगानी पड़ी और इसके लिये काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। हमको मशकूर/कृतज्ञ होना चाहिए किसानों का, जिन्होंने इस देश को इल लायक बना दिया कि हम अपने देश के लोगों को ही मीठा खिला रहे हैं बल्कि अब विदेशों को भी भेज सकते हैं। तो मैं पहला सुझाव यह देना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक और हिन्दुस्तान के जितने सरकारी बैंक है उनको कहा जाय कि गुड़ को खरीदने के लिये कर्जा देने पर कोई पाबन्दी न हो। जो व्यापारी या जो आपके सरकारी निगम गुड़ को खरीदना चाहते हैं, इसके लिये जिस तरह से अन्न की खरीद में आपने हजारों-करोड़ों रुपये लगाये हैं, उसी तरह से आप हजार करोड़ रुपये गुड़-खरीद के लिये निकाल

सकते है । रुपयों की हिन्दुस्तान के बैंकों में कोई कमी नहीं है यह आपको मालूम ही है । हिन्दुस्तान के बैंक 13 हजार करोड़ रुपये का कर्जा देते हैं और अपना काम चलाते हैं । उसमे से सिर्फ एक हजार करोड़ रुपये किसानों को दिया जाता है । तो आप उन बैंकों को चौधरी चरण सिंह के डंडे के हौसले पर सलाह दें कि 1 हजार करोड रुपया गुड़ को खरीदने के लिये निकालना होगा । ताकि हिन्दुस्तान का वह किसान जिसकी आस्था चौधरी चरण-सिंह के ऊपर है, वह बनी रहे । जिसने उस पर आस्था रखकर गन्ने की बुआई की, उसकी आस्था टूटे नहीं । किसान के बल पर ही इतनी बड़ी सरकार आई, आपके पास इतनी शक्ति आई । हमारी आवाज का कोई असर नही था, आपकी आवाज का असर है । तो आपको खंडसारी के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी हटानी चाहिए । यह पहले हटी हुई थी, यह कोई बहुत बड़ी बात नही है । हिन्दुस्तान में एक्साइज ड्यूटी खंडसारी के ऊपर बिल्कुल न हो । आपको ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि ताकि हमे फिर दुबारा बाहर से चीनी न मंगानी पड़े । अगर आपको इसके लिये मदद देनी पड़े तो कोई बात नहीं । सरकार को इसके लिये सौ-दो सौ करोड रुपये घाटे के लिये रखने चाहिए ताकि किसानो को गन्ने का मूल्य सही तौर पर मिल सके । सरकार ने जो 9 रुपये 15 पैसे के हिसाब से गन्ने का मूल्य रखा है, वह इस हिसाब से खरीदा जा सके ।

एक दूसरा सुझाव मैं आपको यह देना चाहता हूं कि कैन कोआपरेटिव यूनियन के मार्फत आप गन्ने को खरीदवायें ताकि किसी क्रैशर का मालिक जो दूसरे के गन्ने को पेरता है, वह सस्ते भाव में न खरीद सके । और कैन कोआपरेटिव यूनियन को जितना पैसा चाहिए गन्ने को खरीदने के लिए वह बैंकों से दिलाइये और उसके अन्दर व्याज की राहत भी दिलाइये । जनता सरकार छोटे-छोटे कारखाने वालों को चार प्रतिशत और बैंक रेट में जितना फर्क होता है यह सरकार सहायता देती है इसी प्रकार गन्ना पैदा करने वाले किसानों को भी ब्याज की राहत दिलाइये । अगर आप नहीं दिला सकते तो आप यह कबूल कीजिए कि अभी भी सरकार के ऊपर आपका कोई असर नहीं हुआ । मैं मानता हूं वित्त मंत्री एक किसान का बेटा हो और पुलिस का डंडा एक किसान के बेटे के पास है । तब भी किसान के हित का अगर संरक्षण नहीं हो सकता तो फिर हिन्दुस्तान के किसानों की प्रजातन्त्र से आस्था उठ जाएगी और प्रजातन्त्र मे आस्था कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि जितना भी रुपया चाहिए किसानों को दिया जाए । आज गेहूं का भाव 125–150 रुपया क्विंटल हो रहा है लेकिन गुड़ का भाव 75 रुपये क्विंटल हो गया है । मै यह पुरानी कहानी यहां पर नही कहना चाहता और न ही यह चाहता हूं कि जनता सरकार मुझे यह कहने का मौका दे । मै इतनी आपसे अवश्य प्रार्थना करता हूं कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दीजिए ताकि जो गुड़ पैदा हो वह खरीदा जा सके । अगर उसमे घाटा भी रहे तो भी कोई बात नही । मान लीजिए 25–50 करोड़ रुपये का सरकार को घाटा रहेगा । एक ओर तो आप सात हजार-दस हजार करोड़ रुपये का गेहूं दूसरे देशों से मंगा कर यहां के 25 प्रतिशत लोगों को खिलाते हैं और हर साल 250–300 करोड़ रुपये की सबसिडी देते हैं तो क्या किसानों के लिए 50 करोड़ रुपये की सबसिडी देने के लिए जनता सरकार बुरा मानेगी ? किसान आपके लिए अनाज पैदा करेगा, मीठा पैदा करेगा जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं जो सुझाव मैने दिए है उनको कार्यान्वित कराइये । अगर इन सुझावों को कार्यान्वित कराने के लिए हमारे झंडे उठाने की आवश्यकता है तो मैं भी झंडा उठा कर आपकी सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं । अगर आप समझते है आपकी सरकार, आपके कृषि मंत्रालय की बात तब तक नही सुनेगी जब तक कुछ आदमी जेल का दरवाजा नही खटखटायेंगे

[श्री रणबीर सिंह]

तो आपकी मदद के लिये हम जेल का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं । लेकिन आप हम से न पूछें क्योंकि आप तो हम से भी ज्यादा समझदार समझे जाते हैं, किसानों के हितों के लिए आपको मानते थे । यह जो एक तर्क है कि मन्त्री बनते ही समझ गहने हो जाती है आप समझ को गहने न कीजिए । आप अवश्य ही हम से कहीं ज्यादा सयाने है । दोनों किसानों के बेटे हो । अब भी किसान लुटेगा तो इससे बढ़ कर बुरा नहीं हो सकता ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरी बातों को या तो सुना नहीं था या समझा नही था । मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार किसी व्यक्ति पूजा की दृष्टि से कोई निर्णय नहीं लेती है । यह आपके शासन काल में होता रहा होगा । चरण सिंह के नाम से गुड को जोड़ना हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता । हम तो आज. . . .

एक माननीय सदस्य : चरण सिंह के डंडे को. . . . .

श्री भानु प्रताप सिंह : डडे का तो आप लोगों को हाल मालूम हो गया है । उसका गुड़ से कोई सबध नहीं है । हम तो केवल रेशनल थिंकिंग करने हैं । मेंटीमेंट की बातें पार्टी का प्रश्न उठाना यह बिलकुल निरर्थक है और मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं । इन बातों पर हमारा कोई भी निर्णय आधारित नही होना चाहिए । आज जो स्थिति है जो इकोनामिक सिचुएशन है उसमें हम क्या तर्कसंगत निर्णय ले सकते है, इस पर हमको विचार करना चाहिए । दूसरी चीज मैं यह बतलाना चाहता हूं, पांच हजार की बात आप कहते हैं गलत फैसला किया । मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गलत किया पर अब तो सुधार लिया है, लेकिन कोई प्रतिबन्ध नही है । हमने तो यह छूट दे रखी है जो जिस भाव पर और जितना भी निर्यात करना चाहे वह कर सकता है । बिजाई की बात आप कहते है । पता नहीं आप कैसे किसान है । हम लोगों की सरकार 23–24 मार्च को बनी थी तब तक सारी गन्ने की बिजाई हो जाती है । यहां का किसान अनपढ़ है इसलिए उसको बराबर गाइडेंस की जरूरत है । अगर वह पढ़ लिखे होते तो हमसे आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं होती । यह सरकार का कर्तव्य था कि वह उन्हें बताती कि अन्तर्राष्ट्रीय भाव क्या है, अगले साल कितनी खपत होगी तथा इसको देखते हुए ही किसान गन्ना बोयें । परन्तु ऐसा नही किया गया । मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह किसानों को बोआई के पहले बताये कि उस फसल के क्या प्रास्पेक्टस होंगे । अगर यह काम किया गया होता तो आज यह मुसीबत नहीं आती । एक्साईज ड्यूटी खांडसारी के लिए जो बात कही गयी है, (*Interruptions*) । गेहूं को बात गेहूं के समय कर लेंगे अभी क्या है । एक्साईज ड्यूटी खांडसारी की बात कही गयी । मैंने बताया कि देशी पर 4 रुपये घटाया है और जो सल्फर खांडसारी है उस पर 10 रुपये क्विंटल है । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि खांडसारी उत्पादकों का स्वयं यह आग्रह था कि पूरी एक्साईज ड्यूटी न हटायी जाए । क्योंकि एक्साईज डयूटी का एक अंश राज्य सरकारों को सेल्स टैक्स के ऐवज में मिलता है । अगर हम पूरी एक्साईज ड्यूटी हटा लेंगे तो राज्य सरकारें सेल्स टैक्स लगा देंगी और वे उस सेल्स टैक्स से ज्यादा घबड़ाते है अपेक्षाकृत इस ड्यूटी से । इसलिए इसमें ज्यादा गुंजाइश नही है और फिर सल्फर वाली और देशी वाली में कुछ अन्तर तो होना चाहिए । इसलिए हमने जहां तक इसको विदड्रा कर लिया है यह उचित है इससे ज्यादा आशा करना. . . . . मान लीजिए कि 2–4 रुपये घट भी जाये तो पूरी इंडस्ट्री पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । इसको राहत देने के लिए अन्य उपायों की आवश्यकता हो सकती है लेकिन एक्साईज

इयूटी से विशेष अन्तर नहीं पड़ने वाला है । श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम लोग निरन्तर इस बात पर विचार कर रहे है । एक सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिया कि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी हो । इस सुझाव पर भी हम विचार कर रहे हैं और संभव है शीघ्र ही निर्णय लेंगे । इसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई तर्कसंगत बात कही गयी हो ।

SHRI SUJAN SINGH (Haryana): Sir, the sharp fall in the prices of gur and khandsari is due to the faulty planning of the Congress Government. The Janata Government has taken over only a year back and it is expected to make improvements on the faulty planning of the Congress Government. Therefore, not only in respect of gur but in respect of other commodities also there is a need for a thorough enquiry as to what faulty programmes are and what their faulty planning is. In respect of wheat also they should see what their wrong planning is. But this will take some time for the Government to make improvements. My hon. friend has suggested many measures and the hon. Minister has given details of what the Government is doing. But I would like to bring one or two points to the notice of the Government.

Firstly, the Government should make a lot of propaganda about the utility of gur. Sir, the utility of gur from food point of view is far superior than sugar. Sugar is injurious to health also, but the common man does not know much about it. Therefore, it needs a lot of propaganda so that the people start consuming more gur than sugar. As a result of this, the consumption of gur would increase in the country and the price of gur will also go up.

Secondly, our Government should not allow further installation of sugar mills. I have read in the papers that the Government is allowing more sugar mills to be set up in different States. Sir, with the coming up of more sugar mills there will be more area under sugarcane cultivation or there will be more production of sugar, and if there is more production of sugar the prices of sugar will also fall and ultimately, the result will be that the price of gur will still go down. Therefore, for the time being no sugar mills should be allowed to come up.

Thirdly, as the hon. Minister has said, there should be regular bulletins on agriculture from the Agriculture Department as it is being done in the U.S.A. and other advanced countries of the world. They issue bulletins on agriculture every month and every season and they tell the farmers as to whether there is the scope of such and such crop, or there is no further scope of growing such and such crop. The farmers will be enlightened and accordingly, they will arrange their crop pattern. This should be a permanent feature of the Department of Agriculture. I think this should have been started long ago during the 30 years of Congress rule. But they did not start this. This is an ordinary thing to start. Had this bulletin been started, the farmers would have been more enlightened by this time and this sort of crisis would not have arisen.

I agree with my friend, Shri Ranbir Singh, that the Government should come out with a huge plan to purchase gur. When it is a question of earning money, Government is keen to nationalise every thing. They can nationalise transport; they can nationalise other industries. It is not clear why Government should not come forward in this case to purchase gur and make arrangements for its storage. If the Government cannot take this up, they should give liberal loans to the farmers and business people so that the gur could be stored. I do not think there is much production of gur in the country even now. There is only a a glut in the country at this stage. The prices may rise after some time. In fact, prices shall rise after some time because there is no provision for its storage. And money is required for storage. So ar-

[Shri Sujan Singh]

rangements should be made for these two things—i.e. monetary help and storage. Then only the prices can be stabilised. There is more need for stabilising prices than anything else in this case.

I do not agree with the hon. Minister regarding possibility of abolition of excise duty on khandsari. There is scope for abolishing the excise duty. Let the excise duty be abolished and the State Governments will take care of it themselves. They will not displease the farmers; and will not come forward to levy the sales tax. The House would also recommend to the State Governments not to levy the sales tax as Government of India would be abolishing the duty only for the sake of farmers and there should be close coordination between the States and the Centre. This position will not arise if the duty is altogether abolished.

There is no question of any politics involved in it. It is only an economic question. Our friends from the Congress Party should give their support to us. We are prepared to take care of this glut and, as the hon. Minister has requested, they should come forward with suggestions rather than saying that they are prepared to go to jail. This is not a matter for going to jail. This is only an economic problem. Let us solve it together.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि कांग्रेस शासनकाल में जो त्रुटियां कृषि के क्षेत्र में हुई हैं, उसके लिए भी कोई जांच कमेटी बैठायी जाए (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : यह क्यों नहीं कहते कि उसी से तो आपके पास इतना स्टाक बढ़ गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं इस जांच कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं समझता । कांग्रेस के लोगों को शाह कमीशन के सामने ही काफी जवाबदेही करनी है ; उसी से निबट लें । इसलिए हम कृषि के क्षेत्र मे जो गलतियां हुई है उसके लिए कोई कमेटी बनाने की बात नही करते है ।

जहां तक यह सुझाव दिया गया कि गुड़ की न्युट्रिशनल वेल्यू के बारे मे एड्वरटाइज किया जाए--कुछ करेंगे भी--लेकिन स्थिति यह है कि अगर गुड़ की खपत ज्यादा हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो चीनी की खपत कम हो जाएगी क्योकि चीनी भी आवश्यकता से कहीं ज्यादा पैदा होने वाली है । तो ये सारी बातें देख कर गुड़ और चीनी की समस्या को हल करना है ।

यह सुझाव कि नयी चीनी मिलों को लाइसेंस न दिया जाए, इस पर हम विचार कर रहे हैं । यह मै स्वयं ही कह चुका हूं कि एक आवश्यक सेवा होगी किसानों के लिए और इसकी शुरुआत करनी चाहिए । गुड़ स्टोरेज का जहां तक संबंध है, यह काफी कठिन है क्योकि इसमें नुकसान हो जाता है । फिर भी, आज ही मैंने विशेषज्ञों को बुलवाया है और अगर कोई रास्ता निकल सकता है बड़े पैमाने पर गुड़ रखने का, तो उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं । एक बात खांडसारी के बारे में कही गयी एक्साइज ड्यूटी के बारे में । इस के लिये हम स्टेट गवर्नमेंट्स से बात कर लेंगे । अगर उन्हें स्वीकार होगा तो फिर हम इस पर विचार कर लेंगे कि उस को और कम किया जाये, परन्तु जैसाकि मै पहले निवेदन कर चुका हूं, इस से स्थिति में कोई विशेष अंतर आने वाला नही है ।

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : माननीय मंत्री जी बार-बार इस बात को दौहरा रहे हैं कि गुड़ उत्पादकों के सामने जो बड़ा संकट पैदा हो गया है, उस के दाम बहुत ज्यादा गिर गये हैं, उन को उचित दाम नही मिल रहे है, उस की खपत नहीं हो रही है वह इसलिये है कि गुड़ पैदा बहुत ज्यादा हो गया है । गन्ना और गुड़ बहुत पैदा हो गया है । अध्यक्ष

महोदय, एक तरफ लोगों को चीनी और गुड़ मिलता नहीं और दूसरी तरफ जो चीनी और गुड़ पैदा होता है वह बिकता नहीं और दलील यही दी जाती है कि पैदा ज्यादा हो गया है। तो यह एक ऐसा तर्क है कि जो इस बात में भी लागू हो सकता है कि आज अनाज नहीं बिक रहा है इसलिये कि किसान ने ज्यादा अनाज पैदा कर लिया है और इस के आधार पर यह नारा दिया जाये कि कृषि की पैदावार कम होनी चाहिए। तो यह एक बुनियादी सवाल है और जो इलाज इस का माननीय मंत्री जी निकालना चाहते हैं कि पैदावार कम कर देने से ही यह समस्या हल हो जायेगी यह इलाज देश को कहां ले जायेगा, यह तर्क देश को कहां ले जायेगा पता नहीं क्योंकि यह सिर्फ गुड़ की पैदावार का ही सवाल नहीं है, दूसरी चीजों की पैदावार का भी सवाल है। मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन बार-बार मंत्री जी ने इस बात को उठाया इसलिये मैंने कहा कि यह सवाल पूरे देश के अर्थ-तंत्र और पूरे देश की अर्थ व्यवस्था का सवाल है। खैर, जहां तक गुड़ का सवाल है, हमारे देश में जो गन्ना पैदा होता है उस का 56 या 60 प्रतिशत गन्ना गुड़ और खांडसारी की पेराई के लिये इस्तेमाल होता है। मात्र 30 से 33 प्रतिशत तक गन्ने की पेराई चीनी के लिये होती है। किसान जो गुड़ या खांडसारी के लिये अपने गन्ने की पेराई करता है वह इस लिये नही कि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन वह इस लिये कि उस की चीनी मिल मालिकों से गन्ने का उचित दाम नहीं मिल पाता। या वक्त पर उनका गन्ना खरीदा नहीं जाता है और इसलिये वे मजबूर होते हैं गुड़ बनाने के लिये या खांडसारी के लिये अपने गन्ने को देने के लिये। इस के बाद बाजार पर बड़े-बड़े व्यापारियों का कब्जा है जो फसल का दाम जब किसान के फसल बेचने का समय होता है तो दाम गिरा देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उस का ही दाम बढ़ा कर वह किसानों को और देश के दूसरे खरीदारों को और खानेवालों को लूटते है। तो गुड़ का दाम जो गिरा दिया गया है उस का एक कारण यह भी है। और यह कारण मौसमी होता है। यह बराबर चलता है। लेकिन यह एक ही कारण है। संपूर्ण कारण यह नहीं है। दूसरे इस के पीछे हमारे देश के चीनी मिल मालिकों की नीति है और जो उनकी साजिश है वह बराबर चलती है जिस की वजह से किसानों को उन का शिकार होना पड़ता है। गुड़ बनाने में भी, चीनी मिलों को गन्ना देने मे भी, कही भी उन को उचित कीमत नहीं मिलती। पिछले साल चीनी मिल मालिकों ने ऊख की जितनी पिराई करने थे उतनी ऊख की पिराई नहीं की। नतीजा यह हुआ कि 20 लाख टन गन्ने की पिराई ज्यादा खांडसारी में करना पड़ा। यह भी एक कारण है जिससे गुड़ की पैदावार बढ़ी। चीनी मिल मालिकों ने किसानों का गन्ना नहीं लिया इसलिए कि चीनी मिल वाले पिछले साल भी सरकार पर दबाव डालते रहे कि गन्ने का दाम कम किया जाए और उनको दूसरी सुविधायें दी जाये और चीनी का लैवी प्राइस और मार्केट प्राइस में कोई भिन्नता न हो और मनमाने तरीके से बाजार में चीनी बेचने की उनको सुविधा दी जाए। ऐसा लगता था कि सरकार मिल मालिकों के सामने झुक जाएगी अन्त में जन-दबाव के चलते सरकार ने चीनी की दौहरी मूल्य के सवाल को तय किया। नतीजा यह हुआ कि किसानों का जो ऊख चीनी मिलों में जाना चाहिए था वह गन्ना पड़ा रहा और उसको गुड़ बनाने के लिए खांडसारी में देने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई। आज भी ये चीनी मिल मालिक सरकार पर दबाव डाल रहे हैं हालांकि सरकार की ओर से 90 करोड़ रुपये की उनको उत्पादन शुल्क में रियायत दी गई है। लेकिन वे फिर भी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि उनको और भी ज्यादा सुविधायें दी जायें, टैक्सों में कमी की जाए। उनको निर्यात और दूसरी चीजों में छूट दी जाए और इसके

[श्री भोला प्रसाद]

लिए उन्होंने जो गन्ना वह खरीदते थे वह भी खरीदना कम कर दिया है । वह मिलों में नही जा रहा है जिसकी वजह से किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है । गन्ना बेचने वाले किसान जिनको साढ़े 13 या साढ़े 12 रुपये मूल्य, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, मिलना चाहिए था वह उनको केवल 5–6 या 7–8 रुपये में चीनी मिल मालिकों को देना पड़ रहा है । इस बात पर सरकार पर्दा डालना चाहती है कि यह जो संकट है इसके पीछे मिल मालिकों का पैदा किया हुआ संकट है और चीनी मिल मालिकों के प्रति सरकार की जो नीति है उसके चलते यह संकट पैदा हुआ है ।

श्री उपसभापति : कृपया संक्षेप में कहिये ।

श्री भोला प्रसाद : तो इन समस्याओं को हल करने की जरूरत है । इसलिए बारबार यह मांग की जा रही है । चीनी मिल मालिकों के सामने सरकार झुकती जा रही है और किसानों की लूटने की पूरी छूट उनको मिलती जा रही है जिसके कारण गन्ना उत्पादकों क ऊपर यह स्थिति आई है । इसलिए बार बार यह सवाल उठता रहा है कि क्यों नही सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करती है । पिछले साल भी और आज भी बराबर इस बात का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है कि सरकार मिल मालिकों के हितों को कायम रखते के लिये ऐसा कर रही है और किसानों को लूटा जा रहा है । तो यह बुनियादी सवाल है जिसे हल किया जाना चाहिए ।

दूसरी चीज तात्कालिक तौर से मैं कहना चाहता हू । माननीय मंत्री जी ने कहा कि फौरन किसानों को मजबूर होकर बहजार में सस्ते में गुड़ बेचने के लिए विवश न होना पड़े जैसा कि व्यापारी चाहते हैं, इसलिए जरूरत है कि स्टोरेज का इन्तजाम हो । मैं कहना चाहता हू कि स्टोरेज का इन्तजाम ही न हो बल्कि किसानों को बैंकों से कर्ज मिले, स्टोरेज की व्यवस्था की जाए ताकि किसान गुड़ को स्टोर कर तत्काल अपना काम चलायें और गिरे हुए दामों पर बाज़ार में बैचने के लिए वह मजबूर न हों । क्या इस काम को सरकार नही कर सकती ? इस काम को अगर सरकार ले तो तात्कालिक तौर पर किसानों को विवश होकर अपना गुड़ बेचने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा । वह अपने पास रख सकते हैं और जब उन्हें अपने गुड़ का उचित दाम मिलेगा तब वह बेच सकते हैं । इसलिये सरकार खुद सपोर्ट प्राइस पर गुड़ खरीदने की व्यवस्था करे । उसके लिये जो प्राइस सरकार ने रखी है उसे बढ़ाना पड़ेगा और कम से कम 125 रुपये क्विंटल गुड़ की सपोर्ट प्राइस निर्धारित करे । नीति निर्धारण में इस के लिये सही माने में पूरी व्यवस्था हो ताकि जिस समय खरीद हो तो किसानों को वही दाम मिले जिससे किसान कम दाम दे कर गुड़ बेचने के लिये मजबूर न हो और व्यापारियों के द्वारा वह लूटा न जाए । यह दो काम सरकार तत्काल कर सकती है । मेरा ख्याल है सरकार को ये दो काम तत्काल करने चाहिये ।

इस संबंध में एक टेलिग्राम आंध्र के एक किसान संगठन की ओर से मेरे पास आया है । उनकी भी यह मांग है कि सरकार गुड़ की सपोर्ट प्राइस निर्धारित करें जिससे कम दाम पर बेचने के लिये किसान मजबूर न हो । हमारा ख्याल है कि सरकार इस पर मुस्तेदी से अमल करेगी ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन, माननीय सदस्य ने एक बुनियादी प्रश्न उठाया है कि गुड़ और चीनी खाने की इच्छा होते हुए भी लोग उसको खरीद नही पाते हैं । इसी प्रकार से अन्न भंडार भरे होने के बावजूद भी बहुत से लोग इस देश में भूखों रहते हैं । यह बात सही है और ऐसा होना नहीं चाहिये ।

परन्तु इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं ? 30 वर्ष के कांग्रेस शासन के बाद आज यह स्थिति है (*Interruptions*) आप सुन लीजिए। धैर्य रखिये। आपने देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगाड़ रखी है कि बहुत से लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है और वह क्रय शक्ति एक दिन में बन नहीं सकती। हम उस क्रय शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रियलटी यह है कि हमें अपनी प्लानिंग में परिवर्तन करना चाहिये। रियलटी यह भी हैं कि हमारे लोगों की क्रय शक्ति कम है और दूसरे विदेशों में इसकी मांग नही हैं। इन रियलटीज को देखते हुए अपनी प्लानिंग होनी चाहिये।

अभी पिराई के विषय में भी कहा गया। यह बात जरूर है कि कुछ मिलें देर में चलीं। इसका कारण यह है कि पहले पिराई के लिये एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दी जाती थी इन्सैन्टिव के रूप में ताकि वह ज्यादा चीनी पैदा करें क्योंकि निर्यात की स्थिति थी और अब निर्यात करने की स्थिति नहीं है। क्योंकि अब निर्यात की स्थिति नहीं है इसलिए कोई रिलीफ एक्साइज ड्यूटी में नहीं दी गई। जब एक्साइज रिलीफ नही दिया गया तो उन्होंने कच्चे गन्ने की समय पर पिराई नहीं की। इसके साथ-साथ हमें राष्ट्रीय हानि भी उठानी पड़ी है। अगर उसकी खपत विदेशों में होती तो संभवतः हम उसे निर्यात करते। थोड़ा नुकसान उठा कर भी करते। लेकिन इस वर्ष कोई खास संभावना नहीं थी कि हम निर्यात कर सकेंगे। इसलिये एक्साइज में जो रिलीफ दी जा सकती थी वह नहीं दी गई और मिलें देर में चालू हुइ। लास्ट ईयर जितनी पिराई हुई थी लगभग उतने तक हम पहुंच गये थे लेकिन चीनी मिल मालिकों से इनकी पुरानी दोस्ती है इसलिये इन लोगों ने उनको समझा-बुझा दिया। फिलहाल उन्होंने मिलें बंद कर दीं। लेकिन हम इनकी दोस्ती से निपट लेंगे ऐसा पूरा विश्वास है। दो-तीन दिनों के अंदर मिलें फिर चालू हो जायेंगी। आपने राष्ट्रीयकरण की बात उठाई है। पिछले सालों में कुछ यों ही राष्ट्रीयकरण का नारा दिया गया था। उसके बाद भी यह परिणाम है कि मिलों का नवीनीकरण नहीं हुआ और वे बड़ी दुर्दशा में हैं। जहां तक जब कोई यह सोचता है कि राष्ट्रीयकृत मिलें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और सरकार को इनके बारे में कोई कठिनाई नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में जो राष्ट्रीयकृत मिलें हैं और जो सहकारी मिलें हैं उनके विषय में हमारे पास रिप्रजेटेशन आ रहे हैं। उन पर विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह मसला यों ही हल होने वाला नहीं है। यह भी सवाल नहीं है कि ओनरशिप किसके हाथ में हो। मसला हमारे सामने यह है कि जरूरत से ज्यादा पैदावार हुई है। हम उस पैदावार से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में जो कुछ संभव है. वह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़ को कैसे रखा जा सकता है. इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों को यह मानना चाहिए कि गुड़ खरीदने की बात पहले पहल सोची जा रही है। यह एक ऐसी कमोडिटी है जिसके संबंध में यह मालूम नहीं है कि इसको कितने समय तक रखा जा सकता है। इसकी तुलना गेहूं या चावल से करना उचित नहीं है और ऐसी तुलना करना नासमझी का परिचय देना है। गेहूं तो पांच या छः वर्ष तक भी रखा जा सकता है और चावल को 30 या 40 वर्ष तक भी रखा जा सकता है। गुड़ को कितने समय तक रखा जा सकता है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि गुड़ को काफी समय तक रखा जा सकता है तो थोड़ा बहुत हानि उठाकर भी हम इसको रखेंगे। लेकिन अगर यह पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है तो फिर इसमें किसी का भी लाभ नहीं है।

श्री रणबीर सिंह : देहातों के अन्दर गुड़ को तीन तीन साल तक रखा जाता था और रखा जाता है।

श्री भानु प्रताप सिंह : अगर ऐसी बात है तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे और यह जान लेंगे कि इसको कैसे रखा जा सकता है। सरकार इन सारी बातों पर विचार कर रही है। अगर गुड़ को काफी समय तक रखने की बात समझ में आ गई तो थोड़ा-बहुत नुक्सान उठा कर भी हम इसको रखेंगे। लेकिन अगर गुड़ रखने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो सरकार इसको नहीं रखेगी।

DR. M. M. S. SIDDHU (Uttar Pradesh): Sir, will the Government revise its dual policy about sugar because the basic point today is that the controls will not yield the result when the production or over-production take place. The question of gur, khandsari and sugar is linked with the farmer's sugar cane. If the farmers are not able to sell their crops and their crops remain standing in the fields, the decision to come to their rescue shall be taken as early as possible. I understand from a reliable source that the price of sugarcane in some parts of Uttar Pradesh has fallen below about Rs. 5 per quintal. Now, with this state of affairs when the mills are not in a position to buy, the khandsari units are not working and gur is being sold at a price which is not profitabe, will the Government think in terms of taking some measures by which khandsari sugar and gur can be subsidised to save the farmer? It is not a question of giving subsidy for khandsari, but to help the sugarcane growers The Government should consider again the question of crop insurance against such fall in prices. It calls for a fair deal or a new deal. Will the Government revise its sugar policy. The policy of the previous Government and even the present Government has been based on scarcity of commodities, and thus, regulations have come in the way of healthy growth.

1 P.M.

श्री भानू प्रताप सिह : श्रीमन, माननीय सदस्य को यह विदित होगा कि जनता सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है जो इस कन्ट्रोल पर विचार कर रही है। उसके अन्तर्गत यहभी आ जायेगा। वह कमेटो जो है वह हमे रिपोर्ट देगी, लेकिन यह पालिसी को तय करने की बात है। लेकिन जहां तक गुड़ की समस्या का प्रश्न है उसका कन्ट्रोल और डी कन्ट्रोल से कोई सीधा सम्बन्ध नही है। सबसीडी वगैरह की जो बात कही गई है, उसके बारे मे मै पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यदि कोई तरीका निकल सकता है इसे रखने का तो यदि इसमें थोड़ा नुक्सान भी उठाना पडे तो भी विचार किया जायेगा। यह जो नुकसान है वह ही सबसीडी होती है। इसलिये माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर विचार हो रहा है।

श्री यशपाल कपूर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, एक मुहावरा है :

'पिदरम सुल्तान बूद'

अर्थात कि मेरा बाप सुल्तान था। इसी तरह यहां सुनने में आता है कि 'पिदरम किसान बूद'

हिन्दुस्तान मे यह सभी समझते हैं कि 99 प्रतिशत किसान के बेटे हैं। बार-बार यह कहना ठीक नहीं है। इसी तरह मै भी कहता हूं कि :

'बाबायेमन किसान बूद'

पाकिस्तान बनने से पहले मेरे दादा भी किसान थे। इस तरह की बात यहां पर बार-बार कहनी ठीक नहीं है। अगर कोई किसान है तो यह बात यहां पर बार-बार कहने की नहीं है। संसद मे जरा यह अच्छा नहीं लगता।

श्री भानु प्रताप सिंह : किसने कहा?

श्री यशपाल कपूर : जिसने भी कहा हो।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैने तो नहीं कह

श्री यशपाल कपूर : श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने एक बडी विचित्र बात कही है कि क्रय शक्ति नहीं है । 80 करोड़ रुपया मिल मालिकों को देकर उसकी खर्च शक्ति आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस 80 करोड़ रुपया उपभोक्ता को देकर कीमत कम नही कर सकते ? पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले राज्य मंत्री जी, आप चीनी मिलों और गुड़ के बारे मे बहुत जानते हैं । गन्ने को किस तरह से राजनीति का हथियार बनाया गया । उत्तर प्रदेश म यह भी आपको मालूम है । वहा पर कई वर्षों से चरण सिह और पृथ्वी नाथ सेठ ने क्या खिलवाड़ किया, और उनका झगड़ा क्यों हुआ उसको सभी जानते हैं । इसमें मैं आपका समय नहीं लेना चाहता । लेकिन साहब, बहुत ज्यादा कीमत थी अन्तर-राष्ट्रीय बाजार मे, यह हो गया, वह हो गया । 1975–76 मे यह हुआ था । 1975 मे खूब विदेशी मुद्रा कमाई, परन्तु 1976 में मामला खतम हो गया और यदि 1978 में उसको लागू करें तो यह बात आपकी बनती नही ।

खैर, गड़ ने निर्यात के बारे में आपने बात कही । मैं समझता हूं कि सभा भवन मे आपने गलत बात कही । गुड़ के निर्यात के लिये आपने कीमत रखी हुई है 35 सौ रुपये टन और यह है एस०टी०सी० द्वारा । आपने जो आर्डर बदला कि खरीद की कीमत की हद खत्म कर दी जाय, मैं मान लेता हूं कि दूनिया मे कोई 35 सौ से ज्यादा मे लेने वाला नहीं है । इसके बारे में एस० टी० सी० ने क्या रिपोर्ट दी, इसको आपने सभा भवन म बताने का कष्ट नहीं किया । आपने यह कह दिया कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के कुछ व्यापारी हैं, निर्यात कर सकते हैं और उनकी संख्या भी निश्चित कर दी । मुझे इस समय ठीक याद नही परन्तु शायद सौ-डेढ़ सौ बम्बई के हैं, 40–50 कलकत्ता के हैं और 20–30 मद्रास के व्यापारी ही निर्यात कर सकते है । क्यों साहब, यह बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के व्यापारी जो हैं उनको किस बात की मोनोपोली दी गई है कि केवल वही निर्यात कर सकते हैं । आपकी इतनी बड़ी सहकारी और सरकारी संस्थायें है । आपने अपने भाषण मे, मुझे खेद हुआ, कष्ट हुआ, अपनी इन सहकारी और सरकारी सभी मिलों को एक दम कंडम करके रख दिया । मे आपसे पूछना चाहता हूं कि यह गन्ने, गुड़ और चीनी का झगड़ा केवल उत्तर प्रदेश मे ही क्यो होता है । यह महाराष्ट्र मे क्यों नहीं होता है । दक्षिण में भी इस तरह की हालत है । महाराष्ट्र में सहकारी शुगर मिलें चलती है । वर्षो से वह चलती चली आ रही हैं । उन्होंने इस देश को चीनी के मामले मे बहुत कुछ दिया है । वहां का गन्ना उत्तर प्रदेश के गन्ने से कही अधिक मोटा रहता है, अधिक लम्बा होता है । उसमे सक्रीन अधिक होती है । उपसभापति जी, हमने करोड़ों रुपया इसकी रिसर्च पर खर्च किया है, इसको फैलाने मे खर्च किया है । परन्तु इस सबके बावजूद आज हालत क्या है ? यह ठीक है कि आपने यह मुकर्रर कर दिया कि गन्ने के दाम 13 रुपये से 15 रुपये प्रति क्विंटल तक होंगे । आप हर एक चीज को सपोर्ट प्राइस पर खरीदने को तैयार हैं लेकिन आज गन्ना 6 रुपये क्विंटल बिक रहा है और उसके लिए आप कुछ न करें, चीनी मिलें बन्द हो गई, क्यों हुई । मेरे साथी भोला प्रसाद जी ने कहा जन दबाव के कारण आपने यह कर किया । जन दबाब की कीमत 80 करोड़ रुपये मिल मालिकों को चुकानी पड़ी । आप जन दबाव की बात मत लाऐं । आपके गांवों में आधा सेर चीनी राशन मे देते हैं वह भी गायब हो जाती है । कहां चली जाती है । शहर के लोग तो एक महीने, दो महीने या छः महीने का राशन खरीद सकते हैं आप उनको यह इजाजत क्यों नहीं देते कि राशन दूकान से जितनी चाहें वे खरीद सकते हैं चाहे साल भर के लिए खरीद लें । इस प्रकार से आपको चीनी बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी । इससे आपकी स्टोरेज की समस्या भी हल हो जाएगी । आप गांव में चीनी फैंक दीजिए । गांव में लोगों के पास क्रय शक्ति बहुत है ।

मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा । गांव में चाहे चीनी पैदा करने वाला किसान है या अनाज पैदा करने वाला किसान है उसको

[श्री यशपाल कपूर]

अगर ठीक दाम न मिले तो चक्की मे कोई पिसता रहता है वह है ग्रामीण मजदूर, जिसको कि पूरे साल भर तो काम मिलता नहीं। जब गन्ने की पिराई हो, गन्ने को काटना हो, चीनी मिल मे पहुंचाने की बात हो, इसी तरह दूसरे अनाज हैं, उनकी बिजाई की बात है, तब कुछ काम मिलता है। अन्न पैदा करने वाले किसान को आज पैसा न मिले जितना उसकी बिजाई पर खर्च हो जाता है तो ग्रामीण मजदूर की हालत क्या होगी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आज इस सभा सदन के द्वारा मैं पूरे राष्ट्र को चेतावनी देना चाहता हूं। आज जो गन्ने के साथ, चीनी के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह सिर्फ किसानों को नही बल्कि इस देश के लाखों ग्रामीण मजदूरों को भूखा करने की स्थिति पैदा की जा रही है और उस स्थिति को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, नही तो ग्रामीण मजदूर आज उठ कर आन्दोलन करने को मजबूर हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस देश मे कुछ किसानों के नये हितैषी पैदा हो गए हैं, जिन्होंने पिछले शासन काल मे किसानों का शोषण करने और करवाने मे कोई कसर न उठा रखी थी। बाकी रही एक्साइज ड्यूटी की बात। तो यह कहना चाहता हूं...

(Interruptions)

श्री यशपाल कपूर : 30 साल से पूंजीवाद की सहायता करते रहे कैसे आदत छूटेगी...

श्री भानु प्रताप सिंह : अभी तो एक साल ही हुआ है . . . *(Interruptions)*

एक गलत बात जो कही गई उसकी मैं यहां पर सफाई दे दूं। यह कहा गया कि हम लोगों ने 80-90 करोड़ रुपये का पूंजीपतियों को उपहार दे दिया है . . . *(Interruptions)*

(Interruption)

जरा सुनिये, कैसे आपकी समझ बढ़ेगी, मेरी समझ मे नहीं आता . . .

(Interruption)

श्री रणबीर सिंह : फिर तो आपको ही समझ बढ़ाने की आवश्यकता है . . .

(Interruptions)

श्री भानु प्रताप सिंह : मै यह कह रहा हूं आप जरा ध्यान दें। पिछले वर्ष अक्तूबर-नवम्बर में खुले बाजार मे चीनी का भाव 480 रुपये क्विंटल था। जिस समय हम लोगों ने निर्णय लिया नयी शूगर पालिसी बनी, उस समय वह घट कर 385 रुपये हो गया था। इस समय 312 रुपये है। क्या आपको इसमें कुछ फर्क दिखाई नही देता? क्या इन मूल्यो के गिरने से एक्साइज ड्यूटी मे रिलीफ देना आवश्यक नहीं दिखाई देता। आप लोग जरा गणित को भी देखें। अब कुछ समझने की कोशिश करेंगे या केवल प्रचार मात्र के लिए सदन से.....

(Interruption)

श्री सुल्तान सिंह : किसान कुछ नहीं देखना चाहता.... *(Interruptions)* किसान मर रहा है और आप दलीलें दे रहे हैं...

(Interruptions)

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, उस समय 480 रुपये पर यही लोग चीनी बिकवा रहे थे। अब बहुत हितैषी बन गए है। गांव में चीनी की बात कही गई। जब तक कांग्रेस शासन चला तब तक गांव वालों को पूरे परिवार को एक किलोग्राम भी चीनी पहुंचाने की बात तो छोड़िये आफिशियली अलाट भी नहीं हुई थी।

श्री कमलापति त्रिपाठी (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, एक बात मैं पूछना चाहता हूं जब 480 रुपये चीनी बिकती थी तो किसानों को ईख की कीमत क्या मिलती थी? अब जब 350 रुपये या 312 रुपये चीनी का भाव हो गया तो किसानों को ईख की कीमत क्या मिल रही है?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं देश की जितनी बड़ी आबादी है—60 करोड़ है या 62 करोड़ है—क्या सारी जनता को खाने के लिए चीनी की जितनी आवश्यकता है वह पैदा होती है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं माननीय त्रिपाठी जी के दोनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से दूंगा। एक प्रश्न तो उन्होंने पूछा कि जब मूल्य 480 रु० पर था तब उनको जो कीमत गन्ने की मिलती थी, वह कीमत अब क्यों नहीं गिरायी है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो किसानों के हितैषी होने का ढकोसला करते हैं वही ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन हम कभी भी किसानों को मिलने वाली कीमत मे कमी होना देखना नहीं चाहते है हम लोगों ने किसानों के हिस्से में कमी न करके सरकार के टैक्स में कमी की है, इसको मेकअप करने के लिए...

(Interruptions)

श्री प्रकाश महरोत्रा (उत्तर प्रदेश) : आप मिलों को बात करिये खांडसारी की बात करिये...

श्री भानु प्रताप सिंह : देखिए, मिलों की बात और एक्साइज ड्यूटी की बात चल रही है, उस विषय मे मुझे यह कहना है कि जब माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि गन्ने की कीमत क्यों नहीं गिरायी है...

(Interruptions)

श्री यशपाल कपूर : वह गलत बात कह रहे हैं, आपको रिपीट करना चाहिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं यह प्रश्न कर रहा था कि जब 480 रुपये कीमत थी चीनी की, तब गन्ने का उत्पादक किसान जो था उसको गन्ने की क्या कीमत मिल रही थी और आज जब आपने घटा कर—इसको आप कहते हैं कि गणित नहीं देखते हो—312 रुपये कर दिया तो गन्ने की कीमत 6 रुपये हो गयी है।

श्री भानु प्रताप सिंह : 6 रुपये गन्ने की कीमत कहीं नहीं है सिवाय कहीं इक्का-दुक्का खांडसारी के विषय में होगा।.... *(Interruptions)* देखिए आप दोनों चीजों को कन्फ्यूज न करिये। फैक्टरी के गन्ने की बात हो रही है, जो बड़ी मिले हैं उनमें कहीं 6 रुपये नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री प्रकाश महरोत्रा : 6 रुपये छोड़िये वह तो दाम भी नहीं दे रहे हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : दाम तो दिलाया जायगा, उसमे आप संतोष रखिए। जो दाम तय होगा वह उनको दिलाया जायगा। दाम पहले से बकाया रह जाता है इसके लिए अभी-अभी हम लोगों ने आदेश जारी किये हैं कि दाम पर सूद भी दिलाया जायगा 15 फीसदी की दर से, इसलिए आप इसकी चिंता न करें। हमने यह भी कहा है कि केन यूनियन जो आपके शासन काल मे गन्ने को रिटेन कर लेती थी, उस पर भी किसानों को सूद दिलाया जायेगा...

(Interruptions)

श्री यशपाल कपूर : क्या निश्चित दाम किया जिस पर कि सूद मिले ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मै यह बताता हू कि जब 480 पर गन्ना बिक रहा था तो उत्तर प्रदेश के पूरब और पश्चिम में सवा 12 और 13 था और आज सवा 12 और सवा 13 है, जबकि गन्ने का मूल्य बढ़ा है और शक्कर का गिरा है।

श्री प्रकाश महरोत्रा : मान्यवर, खांडसारी के लिए आपने गन्ने का...

(Interruptions)

श्री भानु प्रताप सिंह : देखिए, आप अलग-अलग... आप या तो दोनों बहस कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नही है, लेकिन दोनों को कन्फ्यूज न कीजिए। मै बड़े कारखानों की बात कह रहा हूं। खांडसारी एक अनियंत्रित अन-आर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसको हम नियंत्रित करने की कोशिश करते....

(Interruptions)

एक माननीय सदस्य : कुछ किया है या नहीं।

श्री प्रकाश महरोत्रा : आपने दाम फिक्स किया है।

श्री भानु प्रताप सिंह : लेकिन मैं यह बताता हूं कि सैकड़ों खांडसारी वालों के चालान हुए हैं और उन पर मुकदमें चल रहे हैं।

कमलापति त्रिपाठी : क्या करें वह नहीं दे सकते हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : चीनी के वितरण के विषय में मैं बतलाना चाहता हूं कि भूतपूर्व शासन काल में जो एलाटमेंट होता था, वह शहर वालों को जितना मिलता था उसकी तुलना में पांचवां हिस्सा भी गांव वालों के लिए एलाट नहीं होता था, मिलने-मिलाने की बात तो छोड़िए । यह पहला अवसर है कि जनता सरकार ने सारे देश में गांव और शहर के रहने वालों के लिए बराबर 425 ग्राम प्रति माह चीनी देने के आदेश जारी किये है...

(Interruptions)

श्री प्रकाश महरोत्रा : गन्ने का प्रोड्क्शन बढ़ा है, इसलिए आप कर रहे हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : प्रोड्क्शन बढ़ने का प्रश्न नही है । आप 300 ग्राम पर भी बांटते थे, लेकिन आपने कभी एक निगाह से गांव वालों या शहर वालों को नही देखा और आज बात कुछ सूझने लगी है....

(Interruptions)

श्री रणबीर सिंह : आप गुड़ खरीद सकते हैं या नहीं, यह सवाल है ।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1978.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1978, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st February, 1978."

Sir, I lay the Bill on the Table.

Reference to likely retrenchment of Teachers on account of the introduction of the 10+2+3 System

DR. V. P. DUTT (Nominated): Mr. Deputy Chairman, I should like to mention to the Government the grave threat to a large number of teachers in our educational institutions of impending retrenchment. Sir, my honourable freind, Dr. Ram Kripal Sinha is here... *(Interruptions)* .... Mr. Sinha, would you please lend me your ears?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): Yes, I am listening to you.

DR. V. P. DUTT: I am talking of matter which will be of grave concern to you very soon.

Sir, there is considerable confusion which continues to persist in the country with regard to the 10+2+3 system and in many universities, because of a sharp decline in admissions in the coming year, there is an immediate and imminent danger of a large number of teachers being thrown on the streets, thrown out of their jobs, on the ground of their being surplus teachers. In some places, where there are junior colleges, the addition of a year in the course has created problems for these junior colleges and in some other places like Delhi, for instance, teachers, even when substantive posts were available, were appointed only on a temporary basis because of the possible shortfall in admissions. Therefore, I would like to submit to the Government that there is increasing concern that a very large number of teachers may be thrown out of their jobs as a result of the confusion that is now prevailing. Previously, there were assurance given by the Government and by the various educational institutions that there would be no retrenchment. But it seems that all those assurances are being forgotten and at present, no assurance is being given. I should, therefore, like to caution the Govern-